भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1214
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024

1214. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दाहोद जिले के स्कूलों और छात्रों ने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में भाग लिया और उनकी गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ;
(ख) दाहोद जिले में पीएम-उषा योजना के अंतर्गत लाभान्वित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार ने दाहोद जिले में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) दिसंबर, 2024 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, एनसीईआरटी द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया था ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः ग्रेड 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझा जा सके।

सर्वेक्षण को भारत में अधिगम परिणामों पर एक प्रणाली-स्तरीय चिंतन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण योग्यता, कौशल या बुनियादी ढाँचे की कमियों को रेखांकित करता है। यह नीति निर्माताओं को छात्र, शिक्षक और स्कूल प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त अधिगम परिणामों और प्रासंगिक चरों के संबंध में पर मज़बूत, ज़िला-स्तरीय डेटा प्रदान करता है ताकि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए साक्ष्य-आधारित उपाय तैयार किए जा सकें।

देश भर में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक छात्रों और 2.70 लाख शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों ने इस सर्वेक्षण में भाग लिया। दाहोद जिले से,

120 विशिष्ट स्कूलों के कुल 3,530 छात्रों और 417 शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दाहोद के प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

- आधारभूत स्तर पर, दाहोद ने भाषा (60%) और गणित (54%) दोनों में राज्य (गुजरात) के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कि निपुण भारत मिशन जैसी आधारभूत शिक्षण पहलों के तहत किए गए प्रयासों का सकारात्मक प्रदर्शन है।
- प्रारंभिक चरण में, दाहोद का प्रदर्शन राज्य के औसत के बराबर है। तथापि भाषा के अंक थोड़े कम (49%) हैं, लेकिन ज़िले ने "हमारे आसपास की दुनिया" (45%) में बराबरी बनाए रखी है और गणित (41%) में राज्य से थोड़ा आगे रहा है, जो प्रारंभिक चरण में स्थिर शैक्षणिक प्रगति का संकेत देता है।
- मध्य चरण में, ज़िला राज्य के औसत प्रदर्शन से पीछे है। उदाहरण के लिए, भाषा (40%), गणित (28%), विज्ञान (31%) और सामाजिक विज्ञान (31%) में दाहोद के अंक राज्य के औसत अंकों से कम हैं।

(ख) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में रूसा का तीसरा चरण शुरू किया है। इसका परिव्यय 12,926.10 करोड़ रुपये है, जिसमें रूसा के पिछले चरण की प्रतिबद्ध देनदारियाँ भी शामिल हैं। यह अवधि 2023-24 से 2025-26 तक रहेगी ताकि शैक्षिक रूप से वंचित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पीएम-उषा के अंतर्गत, फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। फोकस जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिनमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, जेंडर समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले आदि शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत, गुजरात के दाहोद जिले में विभिन्न घटकों के अंतर्गत 12.74 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय अंश के लिए 4 इकाइयों को अनुमोदित किया गया है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**चरण**	**घटक**	**अनुमोदित इकाई**	**अनुमोदित कुल केंद्रीय अंश (करोड़ रुपये में)**

1	रूसा	पूर्ववर्ती एमडीसी	राजकीय विज्ञान महाविद्यालय, जालोद, दाहोद	1.34
2	रूसा	मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन	नवजीवन साइंस कॉलेज, दाहोद	2.40
3	पीएम-उषा	कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान	नवजीवन साइंस कॉलेज, दाहोद	3.00
4	पीएम-उषा	जेंडर समावेशन और समानता पहल	दाहोद (एक इकाई के रूप में जिला)	6.00

(ग) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा - का क्रियान्वयन कर रहा है। यह योजना बालवाटिका से कक्षा 12 तक स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से देखती है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करती है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार वार्षिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं और फिर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा पूर्व में स्वीकृत उपायों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार उनका मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, दाहोद सहित गुजरात के सभी जिलों में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत कुल 2747.95 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है, जिसका कार्यान्वयन एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है और यह डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करके देश भर में शिक्षा तक बहु-विध पहुँच को सक्षम बनाता है। इन पहलों के घटक गुजरात सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों के उपयोग, निगरानी और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाले पीएम ई-विद्या के

प्रमुख घटकों में से एक, 200 डीटीएच टीवी चैनलों और 400 रेडियो चैनलों का प्रसारण शामिल है, जिससे गुजरात सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 तक के बच्चों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। ये चैनल एनसीईआरटी के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों को आवंटित किए गए हैं और कार्यरत हैं।

उपर्युक्त के अलावा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख अधिकार-आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य बालवाटिका और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत दाहोद जिले में कुल 3.39 लाख छात्र शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार ने दाहोद जिले में शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की निगरानी, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए "ज्ञान सहायक योजना" के तहत शिक्षकों की भर्ती, गुजरात शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जीसीईआरटी) द्वारा सेवारत, नवनियुक्त और प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, योग्यता-आधारित प्रश्न बैंक की तैयारी - जिसमें उच्च क्रम का चिंतन कौशल (एचओटीएस) प्रश्न भी शामिल हैं - और शिक्षकों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जीसीईआरटी वेबसाइट पर इसकी प्लेसमेंट, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी) के प्रसारण के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (एसओई) पहल के तहत वास्तविक और डिजिटल दोनों सुविधाओं का प्रावधान करना शामिल है।

******